जगदीश और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 3377/2001)

फरवरी 12, 2008

(तरुण चटर्जी और आफताब आलम, जे.जे.)

कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1974 रू

धारा 121ए-उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति - भूमि सुधार अधिनियम की धारा 121ए के तहत धारा 115 सीपीसी की तुलना में अधिक व्यापक है - धारा 121ए के तहत। उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरणों के आदेशों की वैधानिकता या कार्यवाही की अनियमितता को देखने और निर्णय में बताई गई परिस्थितियों में रिकॉर्ड पर साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने का अधिकार है - तथ्यों पर, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है उच्च न्यायालय ने, अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द करना उचित नहीं ठहराया - रिकॉर्ड पर साक्ष्य और सामग्री ने स्पष्ट रूप से

स्थापित किया कि फॉर्म -7 दाखिल करने वाले आवेदक यह साबित नहीं कर सके कि वे अनुसूचित भूमि के किरायेदार थे। अनुसूचित भूमि की स्थिति-उच्च न्यायालय ने सही माना कि न्यायाधिकरणों द्वारा आरटीसी रिकॉर्ड में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ दावेदारों द्वारा खेती की गई अनुसूचित भूमि नहीं दिखाती हैं और न ही किरायेदारों की खेती की प्रकृति को दर्शाती हैं - अन्यथा भी, उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष ठीक हैं योग्य है, यह संविधान के अनुच्छेद 136 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा एस. 115- भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

अपीलकर्ताओं के पिता ने भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष फॉर्म नंबर 7 दायर कर यह घोषणा करने की प्रार्थना की कि उन्होंने अनुसूचित भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार हासिल कर लिया है। आरटीसी रिकॉर्ड में प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए उन्होंने दावा किया कि वह 1968 से अधिसूचित तिथि तक उक्त भूमि पर द्वारा के आधार पर खेती कर रहे थे और प्रतिवादी संख्या 4 को उपज में 1/3 हिस्सा देते थे। प्रत्यर्थी क्रमांक 4 द्वारा यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया गया कि यह जमीन है। प्रतिवादी संख्या 3 के पास गिरवी रखी गई थी और उक्त गिरवी की समाप्ति के बाद गिरवीदार अपना कब्जा वापस देने के लिए उत्तरदायी होगा चूंकि गिरवीदार बाद में दूसरे राज्य में बस गया, इसलिए उसकी सहमति से

जमीन 1968 से अपीलकर्ताओं के पिता को खेती के लिए दी गई, लेकिन किरायेदार के रूप में नहीं। भूमि न्यायाधिकरण ने, अन्य बातों के अलावा, आरटीसी रिकॉर्ड में प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं के पक्ष में अधिभोग अधिकार प्रदान किए। प्रतिवादी क्रमांक 4 की अपील अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई। लेकिन, उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता या उनके पिता अनुसूचित भूमि के संबंध में किरायेदारी साबित करने में विफल रहे थे।

इन अपीलों में, अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया गया था कि कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1974 की धारा 121 ए के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय के लिए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है भूमि न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया

1.1 कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1974 की धारा 121ए के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति से अधिक व्यापक है। अधिनियम की धारा 121ए के तहत, उच्च न्यायालय को नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के आदेशों की वैधता या कार्यवाही की नियमितता

पर गौर करने का अधिकार है। संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, उच्च न्यायालय केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के मामलों में न्यायाधिकरणों या निचली अदालतों के आदेशों में हस्तक्षेप करने का हकदार है, जब उसे पता चलता है कि उन्होंने (ए) ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो निहित नहीं है। उनमें कानून द्वारा, या (बी) इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में असफल रहे, या (सी) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्य किया। [पैरा 9] [747 डी एच 748 ए]

1.2 अधिनियम की धारा 121ए के तहत उच्च न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि जब वह रिकॉर्ड पर मौजूद तात्विक साक्ष्यों पर विचार करता है और जब उसे पता चलता है कि ऐसे साक्ष्यों पर नीचे के न्यायाधिकरणों द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था या जब नीचे के न्यायाधिकरणों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत है या जब उसे पता चलता है कि ऐसे सबूतों पर विचार नहीं किया गया है। नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या कि नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए कारण बिल्कुल विकृत हैं या निष्कर्ष ऐसा था कि कोई भी अदालत ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी या कि नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण थे। इसलिए, अधिनियम की धारा 121ए के तहत,

इनमें से किसी भी परिस्थिति की उपस्थिति में, उच्च न्यायालय को इस सवाल पर निर्णय लेने में लगाए गए आदेशों की वैधता पर गौर करने का अधिकार दिया गया था कि क्या अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के तहत किरायेदार माना जा सकता है। [पैरा 9] [748 बी सी डी ई]

दहया लाल एवं अन्य बनाम रसूल मोहम्मद अब्दुल रहीम (1963) 3 एससीआर 1, मोहन बालाकु पाटिल और अन्य बनाम कृष्णाजी भाऊराव हुंड्रे (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि। (2000) 1 एससीसी 518 और कृष्टप्पा येलप्पा पुजार और अन्य। बनाम राम संस्थान बेलाधाडी (1999) 1 एससीसी 74 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

2.1 उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की सावधानीपूर्वक जांच पर, जो रिकॉर्ड पर जो मौजूद तात्विक साक्ष्यों पर आधारित थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को अलग रखना उचित नहीं था। अधिनियम की धारा 121ए के तहत इसके क्षेत्राधिकार का उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करेगी कि अपीलकर्ता यह साबित करने में सक्षम नहीं थे कि वे प्रतिवादियों के तहत अनुसूचित भूमि के संबंध में किरायेदार थे। यह तय करने के लिए मुख्य मानदंडों में से एक यह है कि कोई विशेष व्यक्ति किरायेदार है या नहीं, यह देखना है कि किराए का भुगतान नकद या वस्तु

के रूप में किया गया था या नहीं। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता किसी भी भुगतान के लिए अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहे कि किराया या तो अपीलकर्ताओं के पिता द्वारा या स्वयं अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया था। [पैरा 11] [748 जी एच 749 ए बी सी]

2.2 निचले न्यायाधिकरण निश्चित अवधि के संबंध में आरटीसी रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों पर निर्भर थे। ऐसी प्रविष्टियों पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने सही माना कि वर्ष 1968 से 1974 तक आरटीसी रिकॉर्ड में प्रविष्टियों से, अपीलकर्ताओं या उनके पिता को विवाद में भूमि की खेती करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया था और अनुसूचित भूमि की खेती की प्रकृति को भी उक्त आरटीसी रिकॉर्ड में किरायेदारों की तरह सा नहीं दिखाया गया था। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आरटीसी अभिलेख में की गई प्रविष्टियां उनके दावे का समर्थन नहीं कर सकतीं कि वे किरायेदार के रूप में विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे। [पैरा 12] [749 सी डी ई]

2.3 यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 3 ने, वास्तव में, ई अनुसूचित भूमि को अपीलकर्ताओं या उनके पिता, फसल हिस्सेदारी के आधार पर और अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी नंबर 3 को जिनी का भुगतान किया था। उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के अनुसार, यह नहीं

माना जा सकता है कि अनुसूचित भूमि एफ के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा दावा की गई किरायेदारी स्थापित की जा सकती है। [पैरा 12] [749 ई एफ जी]

3. यह मानते हुए भी कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को अलग करना उचित नहीं था, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, अपीलीय प्राधिकारी और भूमि न्यायाधिकरण के आदेशों और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय था। नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द करना उचित और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्री के अनुसार प्रतीत होता है। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिनियम की धारा 121ए के तहत पारित उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का उपयुक्त मामला नहीं है। [पैरा 15-18] [751 डी ई एफ जी 752 बी ई]

भारत संघ एवं अन्य बनाम गंगाधर नरसिंगदास अग्रवाल एवं अन्य (1997) 10 एससीसी 305, जय मंगल उराँव बनाम. मीरा नायक (श्रीमती)

एवं अन्य (2000) 5 एससीसी 141 और तहेराखातून (डी) एलआरएस द्वारा बनाम सलामिन मोहम्मद (1992) 2 एससीसी 635 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 3377/2001

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु के एल.आर.आर.पी.संख्या 2420/1990 के निर्णय और आदेश दिनांक 20.7.2000 से।.

एन.डी.बी. राजू, भरत राजू और गुंटूर प्रभाकर अपीलकर्ता।

एस. एन. भट, संजय आर. हेगडे, विक्रांत यादव और अमित कुमार चावला प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय तरूण चटर्जी, जे. द्वारा सुनाया गया ।

1. हमारे विचार में, हालांकि उच्च न्यायालय ने धारा 121ए के तहत अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1974 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों द्वारा निकाले गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया था। अधिनियम के अनुसार, फिर भी, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां यह न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के ऐसे आदेश में हस्तक्षेप करेगा।

2. इस अपील में अपीलकर्ता, राज्य के मधुगिरि तालुक के लिंगबहल्ली गांव में स्थित सर्वेक्षण संख्या 125/1 वाली कृषि भूमि के किरायेदार होने का दावा करते हैं, जिसकी माप 3 एकड़ 11 गुंथास (इसके बाद इसे अनुसूचित भूमि कहा जाएगा) है। कर्नाटक के लोगों ने भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष फॉर्म नंबर 7 दायर कर यह घोषणा करने की प्रार्थना की कि उन्होंने अनुसूचित भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार हासिल कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे 1968 से अधिनियम के तहत अधिसूचित तिथि तक वारा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 को खाद्यान्न में एक तिहाई हिस्सा देकर अनुसूचित भूमि पर खेती कर रहे थे। तदनुसार, अपीलकर्ताओं ने अनुसूचित भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार के आदेश के लिए प्रार्थना की और आरोप लगाया कि वे और उनके पिता अधिभोग अधिकार धारकों के रूप में अनुसूचित भूमि पर खेती कर रहे थे, अन्य बातों के अलावा, आरटीसी रिकॉर्ड के तहत प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए।

3. अपीलकर्ताओं का मामला, जैसा कि बताया गया है, वह प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा विवादित था। प्रतिवादी संख्या 4 का मामला यह था कि अनुसूचित भूमि को वर्ष 1968 में और समाप्ति के बाद तीसरे प्रतिवादी, राजाशंकर को गिरवी रखा गया था। उक्त बंधक का, गिरवीदार उस पर कब्जा देने के लिए उत्तरदायी था। अपीलकर्ताओं या उनके पिता द्वारा बनाए

गए किरायेदारी के मामले को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 3 एक फिल्म अभिनेता था और मद्रास (अब चेन्नई) में बस गया था, इसलिए प्रतिवादी नंबर 3 की सहमति से अनुसूचित भूमि उसके पिता को दे दी गई थी। अपीलकर्ता और अपीलकर्ता के पिता वर्ष 1968 से उस पर खेती कर रहे थे, लेकिन किरायेदार के रूप में नहीं। तदनुसार, उन्होंने अधिनियम के तहत अधिभोग अधिकारों का दावा करने वाले अपीलकर्ताओं के पिता द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने की प्रार्थना की। प्रारंभ में, भूमि न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं के पिता के आवेदन को स्वीकार कर लिया और व्यथित महसूस करते हुए, उक्त आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया था और मामले को नए फैसले के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया था। भूमि न्यायाधिकरण ने, रिमांड के बाद, आरटीसी रिकॉर्ड में प्रविष्टियों और रिकॉर्ड पर कुछ अन्य सामग्रियों पर भरोसा करते हुए, अपीलकर्ताओं के पक्ष में अधिभोग अधिकार प्रदान किए।

4. व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई और उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों

को खारिज कर दिया था और अपीलकर्ताओं के पिता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, अन्य बातों के साथ-साथ, कि अपीलकर्ता या उनके पिता अनुसूचित भूमि के संबंध में किरायेदारी साबित करने में विफल रहे हैं। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिसमें आवेदन की अनुमति देने वाले समवर्ती आदेशों को रद्द कर दिया गया था, जिसके संबंध में छुट्टी पहले ही दी जा चुकी है।

5. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजू और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एसएन भट्ट को सुना है। हमने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ न्यायाधिकरणों के आदेशों की भी जांच की है। यह सच है कि उच्च न्यायालय ने, अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, भूमि न्यायाधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी के तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया था, फिर भी, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की जांच की जा रही थी। और अधिनियम की धारा 121ए के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में प्रदत्त शक्ति पर विचार करते हुए, हमें अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

संविधान का ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसले के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले -

> "यह एक निर्विवाद तथ्य है कि पुनरीक्षण याचिकाकर्ता ने 5 वें प्रतिवादी, राजाशंकर के पक्ष में विवाद में भूमि को गिरवी रख दिया है। वर्ष 1968 में और बंधक अवधि की समाप्ति के बाद, चूंकि 5 वां प्रतिवादी विवाद में भूमि का कब्जा वापस देने में विफल रहा, इसलिए उसने मोचन के लिए मुकदमा दायर किया और मोचन के लिए डिक्री प्राप्त की। जब मामला इस प्रकार खड़ा हुआ, प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के पिता गोंडप्पा, जो 5 वें प्रतिवादी, राजशंकर के चाचा हैं, ने भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष फॉर्म नंबर 7 दायर किया और विवाद में भूमि के संबंध में अधिभोग अधिकार का दावा करते हुए तर्क दिया कि वह किरायेदार हैं। उक्त भूमि, वर्ष 1968 से 5 वें प्रतिवादी के अधीन, अर्थात बंधक की तारीख के बाद। इस तथ्य को साबित करने के लिए, उन्होंने 1968 से 1974 के वर्षों के लिए आरटीसी उद्धरण में प्रविष्टियों पर भरोसा किया, जिसमें उनका नाम खेती करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। विवादग्रस्त भूमि का. लेकिन, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त आरटीसी अभिलेख में भूमि की खेती की प्रकृति को किरायेदार के रूप में नहीं दिखाया गया है। एक वर्ष में खेती की प्रकृति का बताया गया है

और वर्षों में कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत आरटीसी उद्धरण उनके इस तर्क का समर्थन नहीं करते हैं कि वह एक किरायेदार के रूप में विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे। उन्होंने यह दिखाने के लिए कोई जेनी रसीद या कोई लीज समझौता प्रस्तुत नहीं किया है कि 5 वें प्रतिवादी ने फसल हिस्सेदारी के आधार पर विवादित भूमि को उनके पक्ष में पट्टे पर दे दिया है और उन्होंने 5 वें प्रतिवादी को जेनी का भुगतान कर दिया है। इस प्रकार, उनके पास अपने दावे के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि वह 5 वें प्रतिवादी के तहत एक किरायेदार के रूप में विवादित भूमि पर कब्जा कर चुके थे और वह एक किरायेदार के रूप में विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे। यह जानना और भी महत्वपूर्ण है कि भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दिए गए साक्ष्य में, उन्होंने दावा किया कि उनके पिता ने याचिकाकर्ताओं के पिता गुंडू राव से वर्ष 1962 में विवादित भूमि पट्टे पर ली थी। यहां तक कि उक्त दावे के संबंध में भी, वह गुंडू राव से विवादित भूमि के पट्टे का सबूत देने वाला कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं 3 और 4 के पिता गोंडप्पा द्वारा दायर फॉर्म नंबर 7 में, उन्होंने आरोप लगाया कि वह वर्ष 1968 से विवादित भूमि के संबंध में 5 वें प्रतिवादी के अधीन किरायेदार थे। किरायेदारी शुरू होने के

वर्ष या जिसके तहत उत्तरदाताओं 3 और 4 के पिता गोंडप्पा किरायेदार बने, के संबंध में कोई सुसंगत रुख नहीं है। तो, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या वर्ष 1968 से 1974 के दौरान उत्तरदाताओं 3 और 4 के पिता द्वारा विवादित भूमि पर की गई उक्त खेती को धारा 4 के प्रावधानों के तहत किरायेदार की भूमि माना जा सकता है। कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम. अधिनियम की धारा 4 यह स्पष्ट करती है कि मालिक के परिवार के किसी सदस्य को डीम्ड किरायेदार नहीं माना जा सकता, भले ही वह मालिक की भूमि पर कानूनी रूप से खेती कर रहा हो। वर्तमान मामले में, चूंकि उत्तरदाताओं 3 और 4 के पिता, प्रतिवादी संख्या 5 के चाचा हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह प्रतिवादी संख्या 5 के परिवार का सदस्य नहीं है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कि प्रतिवादी संख्या 5 और उसके चाचा के संयुक्त परिवार से संबंधित कोई संयुक्त परिवार संपत्ति है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि वे संयुक्त परिवार के सदस्यों के रूप में नहीं रह रहे हैं। इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3 और 4 के पिता गोंडप्पा, जो प्रतिवादी नंबर 5 के चाचा हैं, गिरवीदार, प्रतिवादी नंबर 5 के परिवार के सदस्य नहीं थे।"

6. फिर, उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक निष्कर्षों को खारिज करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष भी निकाले-

"लेकिन वर्तमान मामले में, चूंकि उत्तरदाता 3 और 4 यह दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे कि उनके पिता 5 वें प्रतिवादी गिरवीदार के तहत एक किरायेदार के रूप में विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे और यहां तक कि जब आरटीसी अभिलेख में प्रविष्टियां इस बात का समर्थन नहीं करती हैं। उत्तरदाताओं 3 और 4 के पिता द्वारा स्थापित किरायेदारी का दावा, अधिनियम की धारा 4 के तहत उनके पक्ष में मानी गई किरायेदारी की धारणा बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। उत्तरदाताओं 3 और 4 के पिता, के चाचा हैं प्रत्यर्थी संख्या 5-गिरवीदार, यह भी बहुत संभव है कि उसे उक्त भूमि की खेती में सहायता करके प्रतिवादी संख्या 5 की व्यक्तिगत देखरेख में विवादग्रस्त भूमि पर खेती करने की अनुमति दी गई हो।

वर्तमान मामले में भी, प्रतिवादी 3 और 4 यह साबित करने में विफल रहे कि उनके पिता प्रतिवादी संख्या 5 के तहत किरायेदार के रूप में वर्ष 1968 से विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे और उनके पिता की मृत्यु के बाद, वे किरायेदार

के रूप में बने रहे। विवाद में भूमि के संबंध में ..यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 5, जो उस समय जीवित था जब जांच भूमि न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी, उसने प्रतिवादी 3 और 4 के पक्ष में यह कहते हुए साक्ष्य नहीं दी है कि उसने पट्टे पर दिया है। विवादग्रस्त भूमि को प्रत्यर्थीगण 3 और 4 के पक्ष में कर दिया गया। प्रत्यर्थीगण 3 और 4 की हितबद्ध गवाही के अलावा, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर और कुछ नहीं है कि उनके पिता को 5 वें प्रतिवादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर खेती करने के लिए किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था। विवाद के बाद जमीन को उसके द्वारा गिरवी पर ले लिया गया था। इसलिए, यह मानना संभव नहीं है कि उत्तरदाताओं 3 और 4 के पिता को गिरवीदार, 5 वें प्रत्यर्थी द्वारा विवाद में भूमि के संबंध में किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी 3 और 4 कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे। यह दिखाने के लिए कि उनके पिता को 5 वें प्रत्यर्थी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे किरायेदार के रूप में गिरवी रखा गया था और वे अपने पिता की मृत्यु के बाद उक्त भूमि के संबंध में किरायेदार के रूप में बने हुए हैं, मुझे

लगता है कि वे हैं व्यावसायिक अधिकार देने का हकदार नहीं है..इस न्यायालय के पहले के फैसले में 1996 पृष्ठ 2340 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति यह साबित करने में विफल रहता है कि वह किरायेदार के रूप में भूमि पर खेती कर रहा है, तो इस तथ्य के बावजूद कि उसे व्यावसायिक अधिकार नहीं दिया जा सकता है। भूमि पर कब्जा होना और उस पर खेती करना, वर्तमान मामले के सभी चारों तथ्यों पर लागू होता है।''

6. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों की सावधानीपूर्वक जांच से, जैसा कि यहां ऊपर उद्धृत किया गया है, नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों द्वारा प्राप्त तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को खारिज करते हुए, हम यह मानने की स्थिति में नहीं हैं कि उच्च न्यायालय को स्थापित करने में उचित नहीं था अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के समवर्ती आदेशों को अलग रखें। नीचे दिए गए न्यायाधिकरणों के आदेशों को संशोधित करने के लिए उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति, अधिनियम की धारा 121ए में प्रदान की गई है, जो निम्नानुसार हैः-

''उच्च न्यायालय किसी भी समय ऐसे आदेश की वैधता या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के बारे में खुद को

संतुष्ट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए किसी भी आदेश या कार्यवाही के रिकॉर्ड मांग सकता है। और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे''

8. अधिनियम की धारा 121ए को पढ़ने से, जिसके तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, यह स्पष्ट होगा कि उच्च न्यायालय, ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय सबूतों की फिर से सराहना करने का हकदार है जब उसे पता चलता है कि निष्कर्ष आ गया है अपीलीय प्राधिकारी रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत काम करता है और जब उसे पता चलता है कि अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जब उसे पता चलता है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए कारण बिल्कुल विकृत हैं और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं किए जा सकते हैं रिकॉर्ड पर। अधिनियम की धारा 121ए को पढ़ने से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय भी न्यायाधिकरणों के आदेशों में हस्तक्षेप करने का हकदार है, जब रिकॉर्ड पर तात्विक साक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया गया था या कोई निष्कर्ष ऐसा था कि कोई न्यायालय ऐसा निष्कर्ष या कि न्यायाधिकरणों का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण था।

9. हमने अधिनियम की धारा 121ए के तहत प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच की है, जो अधिनियम के तहत पुनरीक्षण शक्ति है, और सि.प्र.सं. की धारा 115 के तहत प्रावधानों की भी जांच की है। जहां तक सिविल प्रकिया संहिता की धारा 115 का संबंध है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि के मामले में जब निचली अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में तात्विक अनियमितता के साथ काम किया हो तो यदि ऐसे में आदेशों में हस्तक्षेप करने का सवाल उठता है, अन्यथा उच्च न्यायालय को किसी अन्य आदेश में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा जो संहिता की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। दूसरी ओर, हमारे विचार में, अधिनियम की धारा 121ए के तहत उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधिकरणों के आदेशों में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता होगी क्योंकि उच्च न्यायालय को आदेश की वैधता या नियमितता को देखने का अधिकार है। हालाँकि कार्यवाही, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, उच्च न्यायालय आदेश की वैधता या कार्यवाही की नियमितता पर गौर करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन केवल न्यायाधिकरणों या अधीन्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप करने का अधिकारी है। जब वह पाता है कि उन्होंने (क) उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उनमें निहित नहीं है, या (ख) उस निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहे हैं, या (ग) अपने क्षेत्राधिकार के

प्रयोग में अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया है। उपरोक्त प्रावधानों, जैसे अधिनियम की धारा 121ए और संहिता की धारा 115 को पढ़ते हुए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि अधिनियम की धारा 121ए के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई पुनरीक्षण शक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के तहत प्रयोग की गई पुनरीक्षण शक्ति से अधिक व्यापक है। संहिता की धारा 115 के तहत उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में, जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, चूंकि अधिनियम की धारा 121ए स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को आक्षेपित आदेशों की वैधता पर गौर करने का अधिकार देती है, इसलिए, जब उच्च न्यायालय को ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो वह रिकॉर्ड पर मौजूद तात्विक साक्ष्य पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनमें न्यायाधिकरणों द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है या जब न्यायाधिकरणों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों के विपरीत था या जब उसे पता चला कि न्यायाधिकरणों के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है या जो कारण न्यायाधिकरण दिए गए हैं वे बिल्कुल विकृत है या उनका निष्कर्ष ऐसा था कि कोई भी अदालत ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी या कि न्यायाधिकरणों के निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण थे। इसलिए, अधिनियम की धारा 121ए के तहत, उपरोक्त किसी भी परिस्थिति में, उच्च न्यायालय को इस सवाल पर निर्णय

लेने में आक्षेपित आदेशों की वैधता पर गौर करने का अधिकार है कि क्या अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी 3 व 4 का किरायेदार माना जा सकता है।

10. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, समुचित मामले में न्यायाधिकरणों के आदेशों की वैधता की जांच करने के लिए कब न्यायोचित होगा। अब हम न्यायाधिकरणों के तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त करने के संदर्भ में, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की जांच करें तो हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद तात्विक साक्ष्यों पर आधारित थे, के बारे में हमारे लिए यह मानना मुश्किल है कि अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरणों के तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त करने में उच्च न्यायालय के लिए न्यायोचित नहीं था।

11. हमने पूर्व ही इस सवाल पर उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दिए गए निष्कर्षों को नोट कर लिया है कि क्या अपीलकर्ताओं को रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्रियों के आधार पर किरायेदार माना जा सकता है। ऐसा करते समय, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय का इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित था कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करेगी कि अपीलकर्ता यह साबित करने में सक्षम

नहीं थे कि वे प्रत्यर्थियों के अधीन अनुसूचित भूमि के संबंध में किरायेदार थे। यह तय करने के लिए मुख्य मानदंडों में से एक यह है कि कोई विशेष व्यक्ति किरायेदार है या नहीं, इस बारे में यह देखना है कि किराए का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में किया गया था या नहीं। इस मामले में, अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना था कि अपीलकर्ता अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहे थे कि किराए का कोई भी भुगतान या तो अपीलकर्ताओं के पिता द्वारा या स्वयं अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया था।

12. न्यायाधिकरणों ने अपीलकर्ताओं के मामले को स्वीकार करते समय, निश्चित अवधि के संबंध में आरटीसी रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों पर भरोसा किया था। ऐसी प्रविष्टियों पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय ने सही माना था कि वर्ष 1968 से 1974 तक आरटीसी रिकॉर्ड में प्रविष्टियों से, अपीलकर्ताओं का नाम विवादित में भूमि पर खेती करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं दिखाया गया था और न ही खेती की प्रकृति को दर्शाया गया था। उक्त आरटीसी रिकॉर्ड में अनुसूचित भूमि में अपीलार्थी को किरायेदारों के रूप में नहीं दिखाया गया था। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय उचित निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आरटीसी उद्धरणों में प्रविष्टियां इस तर्क का समर्थन नहीं कर सकतीं कि वे किरायेदारों के रूप में विवादित भूमि पर खेती कर रहे थे। हमारे विचार में भी, यह दिखाने के

लिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष 5 वें प्रत्यर्थी (यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 3) ने वास्तव में कोई जेनी रसीद या कोई पट्टा समझौता प्रस्तुत नहीं किया था, अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में उच्च न्यायालय पूरी तरह से उचित था। अनुसूचित भूमि को अपीलकर्ताओं या उनके मृत पिता के पक्ष में फसल हिस्सेदारी के आधार पर पट्टे पर दिया गया था और अपीलकर्ताओं ने 5 वें प्रत्यर्थी को जिनी का भुगतान किया था। उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से हम सहमत हैं, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि अनुसूचित भूमि के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा दावा की गई किरायेदारी स्थापित की जा सकती है।

13. मामले के उपरोक्त पहलू पर विचार करने और अधिनियम की धारा 121ए के दायरे पर विचार करने के बाद, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील से सहमत होने में असमर्थ हैं कि अधिनियम की धारा 121ए के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी और भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द करने का हकदार नहीं था। ऐसी स्थिति होने पर, हमें उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, हालांकि उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलीय प्राधिकारी के साथ ही भूमि न्यायाधिकरण के समवर्ती आदेशों को रद्द कर दिया था।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री राजू ने हमारे सामने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 121 ए के तहत अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, समवर्ती आदेश में हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय के लिए सही नहीं था, जो अपीलीय प्राधिकारी और भूमि न्यायाधिकरण द्वारा तथ्य के निष्कर्ष निकाले गए। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने दहिया लाल और अन्य बनाम रसूल मोहम्मद अब्दुल रहीम 1963 (3) एससीआर 1 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था। उन्होंने मोहन बालाकू पाटिल बनाम कृष्णोजी भाऊराव हंड्रे (2000) 1 एससीसी 518 और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया और कृष्टप्पा येलप्पा पुजार और अन्य बनाम राम संस्थान बेलाधाडी (1999) 1 एससीसी 74 पर भरोसा किया है। हमारे विचार में, जहां तक मोहन बालाकु पाटिल और अन्य बनाम कृष्णोजी भाऊराव हंड्रे (2000) 1 एससीसी 518 के मामले में निर्णय का संबंध है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह निर्णय अपीलकर्ताओं के लिए कैसे मददगार हो सकता है। उस मामले में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारों के रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों पर भरोसा करते हुए इस आशय से पुष्टि की गई कि अपीलकर्ताओं के पास प्रासंगिक तिथि पर भूमि का कब्जा नहीं था और न ही वे खेती कर रहे थे। वही, इस अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, उस निर्णय में, उपरोक्त निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए, इस

न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश को भी रद्द कर दिया था जैसा कि उच्च न्यायालय ने संशोधन में पुष्टि की थी और भूमि न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को बहाल कर दिया था। यदि वह मामला वर्तमान मामले के तथ्यों में कोई मदद करता है, तो यह उत्तरदाताओं के पक्ष में होगा। जहां तक कृष्टप्पा येलापा पुजार और अन्य बनाम राम संस्थान बेलाधाडी (1999) 1 एससीसी 74, का संबंध है, हम फिर से यह समझने में विफल रहे कि यह अपीलकर्ताओं के लिए कैसे मददगार हो सकता है। उस निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों में केवल कानून या प्रक्रिया में अनियमितता के प्रश्न पर ही हस्तक्षेप करने का हकदार था, किसी अन्य पहलू पर नहीं। हमारे विचार में, हम पहले ही मान चुके हैं कि उच्च न्यायालय न्यायाधिकरणों के समवर्ती आदेशों में हस्तक्षेप करने का हकदार था क्योंकि रिकॉर्ड पर तात्विक साक्ष्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था और रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य पर विचार न करना कानून का प्रश्न है और, इसलिए, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने का अधिकार था। तदनुसार, इस निर्णय से अपीलकर्ताओं को कोई मदद नहीं मिलेगी। अंत में, हमारे विचार में, यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, दहया लाल और अन्य के मामले में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया, पर चर्चा की जरूरत नहीं है।

15. इस मामले का एक और पहलू भी है. यहां तक कि यह मानते हुए भी कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 121ए के तहत अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को अपास्त करना उचित नहीं था, हमारा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारी शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिये।

16. भारत संघ एवं अन्य बनाम गंगाधर नरसिंगदास अग्रवाल और अन्य (1997) 10 एससीसी 305, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि भले ही दो विचार संभव हों, उच्च न्यायालय ने एक विश्वसनीय न्यायालय के रूप में जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, वह संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग नहीं करेगा। अपीलीय प्राधिकारी और भूमि न्यायाधिकरण के समवर्ती आदेशों और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश पर विचार करते हुए, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं क्योंकि उसके द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय था, इसलिए अनुच्छेद 136 के तहत हमारे द्वारा व्यक्त किया गया हस्तक्षेप का प्रश्न है अधिपत्रित नहीं है।

17. पुनः जय मंगल ओराँव बनाम मीरा नायक (श्रीमती) और अन्य (2000) 5 एससीसी 141, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि

जब उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और निष्कर्ष में कुछ भी अवैध या गलत नहीं था और वह अच्छी तरह से योग्य और वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के अनुसार प्रतीत होता था, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमने पूर्व में ही न्यायाधिकरणों के समवर्ती आदेशों को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर विचार किया है और पाया है कि यह उचित प्रतीत होता है और रिकॉर्ड पर तात्विक साक्ष्य के अनुसार है, इसलिए यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नही करेगा। अंत में ताहेराखातून बनाम सलामिन मोहम्मद (1992) 2 एससीसी 635,, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 20 में न्यायालय ने पैरा 20 में यह उल्लेख किया है कि

> ''उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर, भले ही अब हम विशेष अनुमति देने के बाद अपील से निपट रहे हैं, हम गुण-दोष में जाने के लिए बाध्य नहीं हैं और भले ही हम ऐसा करते हैं और कानून की घोषणा करते हैं या त्रुटि को इंगित करते हैं - फिर भी हम कर सकते हैं यदि तथ्यों के आधार पर मामले के न्याय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है या यदि हमें लगता है कि राहत को एक अलग तरीके से ढाला जा सकता है तो हस्तक्षेप नहीं कर सकते।''

18. उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा विचार है कि यह उपयुक्त मामला नहीं है जहां यह न्यायालय अधिनियम की धारा 121ए के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करेगा।

19. उपरोक्त कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और हर्जे के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

आर. पी अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपक पांडे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।